



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ५२५]

नई विल्सो, बृद्धकार, विसम्बर ४, १९८५/अग्रहायण १३, १९०७

No. 525] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 1985/AGRAHAYANA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे इक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pagina is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

प्रधिसूचना

नई विल्सो, ४ दिसम्बर, १९८५

सा. का. नि. ८८१ (भ):—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
प्रादेश जनसाधारण की जातकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

‘सं. आ. १२४

मंविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना)

द्वितीय संशोधन, प्रावेश, १९८५

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद ३७० के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त
संविधानों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सह-
मति से, निम्नलिखित प्रावेश करते हैं:—

१. (१) इस प्रावेश का संविधान नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को
नागू होना) द्वितीय संशोधन प्रावेश, १९८५ है।

(२) यह तुरन्त प्रदूष होगा।

२. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) प्रावेश, १९५४ के
पैरा २ में, —

(क) उप-पैरा (४) (जो भाग ३ से संबंधित है) में खण्ड (ए)
का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (२) (जो भाग १६ से संबंधित है) में, —

(१) खण्ड (क) का लोप किया जाएगा,

(२) खण्ड (ब) और (ग) को खण्ड (क) और (ब) के
रूप में पुनः प्रकाशित किया जाएगा, और इस प्रकार
पुनः प्रकाशित खण्ड (क) में, “३३६, ३३७, ३३९
और ३४२” अंकों और प्रकार के स्थान पर “३३६
और ३३७” अंक और प्रकार रखे जाएंगे।

(३) इस प्रकार पुनः प्रकाशित खण्ड (ब) के परवर्ती
निम्नलिखित खण्ड अंक स्थापित किया जाएगा, अधिक:—

“(ग) प्रानुसूचित ३३९ के खण्ड (१) में “राज्यों के
अनुसूचित संघों के प्रयोग से और प्रानुसूचित
जनजातियों” शब्दों के स्थान पर “राज्यों को
अनुसूचित जनजातियों” शब्द रखे जाएंगे।”

अंत सिवा,

राष्ट्रपति

[का. सं. १९ (१)। ८४—पि. १]

इ वेंकट सुर्य प्रियास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
 (Legislative Department)
 NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1985

G.S.R. 881(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 124

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) SECOND AMENDMENT ORDER, 1985

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(a) in sub-paragraph (4) (relating to Part III), clause (b) shall be omitted;

(b) in sub-paragraph (11) (relating to Part XVI),—

(i) clause (a) shall be omitted;

(ii) clause (b) and (c) shall be re-lettered as clauses (a) and (b), and in clause (a), as so re-lettered, for the figures and word "336, 337, 339 and 342" the figures and word "336 and 337" shall be substituted;

(iii) after clause (b), as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

(c) In clause (1) of article 339, the words "the administration of the Scheduled Areas and" shall be omitted.'

ZAIL SINGH,
 PRESIDENT

[No. F. 19(1)/84-LI]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.